राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष 33 | अंक 11 | फरवरी 2012 | मूल्य 5 रु. | पृष्ठ 24

कर्नाटक में आयोजित निजी विश्वविद्यालय गोलमेज चर्चा सत्र में सहभागी शिक्षविद

दिल्ली प्रदेश अधिवेशन में मंचासिन मान्यवर

राष्ट्रीय छात्रशक्ति

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

संपादक

आशुतोष

संपादक मण्डल

अवनीश सिंह
संजीव कुमार सिन्हा

फोन : 011-43098248
ईमेल : chhatrashakti.abvp@gmail.com
ब्लॉग :chhatrashaktiabvp.com
वेबसाईट :www.abvp.org

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के लिए राजकुमार शर्मा द्वारा बी-50, विद्यार्थी सदन, क्रिश्चियन कॉलोनी, निकट पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली - 110007 से प्रकाशित एवं मॉडर्न प्रिन्टर्स, के-30, नवीन शाहदरा, दिल्ली - 110032 द्वारा मुद्रित।

संपादकीय कार्यालय

''छात्रशक्ति भवन''
690, भूतल, गली नं. 21
फैज रोड, करोलबाग,
नई दिल्ली - 110005.

अनुक्रमणिका

विषय	पृ. सं
संपादकीय	4
चिदंबरम् के खिलाफ राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन	5
भ्रष्टाचार का शिष्टाचार	7
'पुणे में आयोजित कश्मीर सेमिनार रद्द	9
'थिंक इंडिया' बेंगलुरू में संपन्न	10
उठो पार्थ, गांडीव संभालो! — प्रो.. राकेश सिन्हा	12
जम्मू–कश्मीर में पूर्व कार्यकर्ता सम्मेलन	15
विदेशी तथा स्वदेशी दृष्टि में शिवाजी — डॉ. सतीश चन्द्र मित्तल	16
जम्मू–कश्मीर पर बिछी सतरंज की बिसात — डॉ. कुलदीप चन्द अग्निहोत्री	20

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय .....

2 फरवरी 2012, को सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 2जी स्पेक्ट्रम मामले में 122 लाईसेन्स रद्द किए यह एक तरफ वर्तमान भ्रष्ट केंद्र सरकार के लिए कड़ा तमाचा था, तो दुसरी तरफ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के लिए बड़ी जीत साबित हुआ। इस फैसले ने सीधे तौर पर उस लाईसेंस की प्रक्रिया को अवैध करार किया जिसमें करोड़ों रूपयों का घोटाला हुआ। स्वाभाविक ही इस प्रक्रिया में शामिल सभी की भूमिका संदेहास्पद स्थिति में पहुँच गयी। सर्वोच्च न्यायालय की इस भावना ने सभी को 2जी मामले की पुरी जाँच की आशा बांधी थी।

लेकिन इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने संबंधित मंत्री चिदंबरम् को आरोपी मानने से मना कर दिया व उनकी जाँच की संभावना को भी स्थगित कर दिया। इस 4 फरवरी के फैसले पुरे देश को अचंभित कर दिया है।

ट्रायल कोर्ट के न्यायमूर्ति श्री सैनी द्वारा अपने फैसले के पैराग्राफ क्र. 66 में यह मान लिया है कि 2001 के दरों पर लाईसेंस देने के फैसले में तत्कालिन वित्तमंत्री शामिल थें व उन्होंने ही श्री ए. राजा के साथ हुई बैठक में उपरोक्त निर्णय लिया व उसे मा. प्रधानमंत्री को अवगत कराया। जिसके बाद ही लाईसेंस की प्रक्रिया प्रारंभ करायी गयी तथा लाईसेंस प्राप्ति पर कंपनियों को उसे ऊंचे दामों पर बेचने (Liquidity) की अनुमति भी उनके संज्ञान में दी गयी। फिर भी एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय उन लाईसेंसों को रद्द कर रहा है। वहीं ट्रायल कोर्ट राजा को तो जेल में रख रहा है लेकिन चिदंबरम् की गतिविधि की गुनाह (Criminal Act) मानने से मना कर रहा है, यह काफी आश्चर्यजनक है।

वैसे केंद्रीय सतकर्ता आयुक्त (CVC) की नियुक्ति हो या राष्ट्रमंडल खेल घोटाले में मुख्यमंत्री शील दीक्षित की भूमिका की जाँच हो, जिन पर कैग रिपोर्ट में सीधी टिप्पणी है, या फिर सीबीआई का दुरूपयोग हो, सारी घटनाएँ चोरी को छुपाने व चोरों को बचाने की नीति को बार–बार उजागर करती है।

जब ए. राजा, कन्निमोझी वैसे बड़े–बड़े नेता हवालात में पहुँच गये। तो लोगों में भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ होगा, ऐसी आशा बढ़ी व आंदोलन में उतर आए। परंतु वर्तमान सरकार लगातार भ्रष्टाचार विरोधी वे आंदोलन के प्रति भ्रम फैलाते हुए कमजोर करने का प्रयास कर रही है। संसद में विपक्ष द्वारा जारी लड़ाई को झुठ करार देते हुए उसे कमजोर करना, विद्यार्थी परिषद् या युथ अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन को राजनैतिक बताना, काले धन के खिलाफ लड़ रहे बाबा रामदेव के उपर हमला व उन्हे बदनाम करना, अन्ना हजारे के 'लोकपाल' हेतु चल रहे आंदोलन के साथ धोखा करना, जैसी सारी घटनाएँ सरकार की मंशा स्पष्ट करती है। लेकिन इससे भ्रष्टाचार के खिलाफ आम लोगों के मन में कुंठा बढ़ रही है, व आक्रोश भी बढ़ रहा है।

लोकपाल के परे जाकर (beyond Lokpal) व्यापक एवं गंभीर लड़ाई की जरूरत साफ नजर आ रही है। अन्यथा जैसे बोफोर्स की जाँच जो कभी अपने मुकाम पर नहीं पहुँच पायी, वैसा ही कुछ हश्र 2जी मामले का हो सकता है। इसलिए वर्तमान सरकार में बैठे लोग शायद ट्रायल न्यायालय के चिदंबरम् को आरोपी न बनाने के फैसले को राहत या अपनी जीत मान रहें होगे, लेकिन युवाओं को यह गलत साबित करना होगा। एक ऐसा तूफान भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा करना होगा, जो परिवर्तन की शक्ति रखेगा। देश के लोगों की यहीं अपेक्षा इस पिढ़ी से है।

भ्रष्ट गृहमंत्री के खिलाफ राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन

'चिदंबरम इस्तीफा दो' के नारों से गूंजे शिक्षा परिसर

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् एवं यूथ अगेंस्ट करप्शन ने देश के भ्रष्ट गृहमंत्री पी. चिदंबरम को 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में संलिप्त होने के प्रमाण मिलने के बाद सह अभियुक्त बनाने, पद से तुरंत हटाने व गिरफ्तार करने की एकसूत्रीय मांग को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। 'चिदंबरम इस्तीफा दो' के नारों से गूंजती लाखों युवाशक्ति की आवाजों के साथ 18 जनवरी को देश के सैकड़ों स्थानों पर एक साथ विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया।

दिल्ली में जंतर–मंतर पर विरोध प्रदर्शन करते अभाविप कार्यकर्ता

दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर–मंतर पर आयोजित विराट प्रदर्शन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री श्री उमेश दत्त ने कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम की जाँच को प्रभावित कर कांग्रेस घोटाले के लिए जिम्मेदार अपने पार्टी के मंत्री चिदंबरम को बचाने की कोशिश कर रही है। चिदंबरम के तुरंत इस्तीफे की मांग करते हुए श्री उमेश दत्त ने कहा कि अगर चिदंबरम तुरंत इस्तीफा नहीं देते तो मार्च महीने में आयोजित संसद सत्र के दौरान विद्यार्थी परिषद् और यूथ अगेंस्ट करप्शन राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेगी जिसमे चिदंबरम के साथ–साथ पुरे युपीए सरकार को जाना पड़ेगा। वर्तमान सरकार को भ्रष्टाचार की सारी हदें पार करने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय मंत्री श्रीरंग कुलकर्णी ने कहा की कांग्रेस अपनी पार्टी के दोषियों को बचाने के चक्कर में सहयोगियों को बलि का बकरा बना रही है तथा सुनियोजित तरीके से देश का धन लुटने की कोशिश में दिन रात लगी हुई है। दिल्ली प्रान्त संगठन मंत्री डॉ. योगेन्द्र पयासी ने कहा की विद्यार्थी परिषद् चिदंबरम के करतूतों का पुरे देश में खुलासा करेगी तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक संघर्ष के संकल्प को पूरा करेगी।

जम्मू–कश्मीर के कठुआ, साम्बा, उधमपुर सहित पुरे प्रदेश में बड़ी संख्या में विद्यार्थी प्रदर्शन हेतु सड़कों पर निकलें व चिदंबरम का पुतला दहन कर इस्तीफे की मांग

जम्मू में विरोध प्रदर्शन करते अभाविप कार्यकर्ता

की। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जम्मू–कश्मीर के प्रदेश मंत्री राघव शर्मा ने कहा की 2जी में 1.76 लाख रुपयों की क्षति के जिम्मेदार चिदंबरम को तुरंत इस्तीफे दे देना चाहिए। मध्यभारत प्रान्त के 65 स्थानों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित हुए जिसमें देश को हुए आर्थिक नुकसान से आक्रोशित युवाओं ने भ्रष्ट गृहमंत्री चिदंबरम की शव यात्रा निकाली व पुतला दहन किया। शवयात्रा ज्योति टॉकिज चौराहे से बोर्ड ऑफिस चौराहे पहुँच एक बड़े जनसभा में तब्दील हो गयी। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए प्रान्त मंत्री सुश्री भारती कुंभारे ने कहा की जानकारी रहने के बावजूद स्पेक्ट्रम आवंटित होने देना घोटाले में शामिल होने का प्रमाण है। उन्होंने राष्ट्रपति से गृहमंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरू, चंडीगढ़, शिमला, पटना, लखनऊ, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, रायपुर, जबलपुर सहित देश भर के सभी प्रांतों के कई स्थानों पर चिदंबरम् को सह अभियुक्त बनाने व गिरफ्तार करने के मांग को लेकर प्रदर्शन किए गए जिसका नेतृत्व अभाविप के केंद्रीय व प्रांतीय पदाधिकारियों ने किया। पूरे देश में आयोजित इस प्रदर्शन में उमड़ी युवाशक्ति व भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी आक्रोश से यह स्पष्ट हो गया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लंबी लड़ाई के लिए देश की युवा शक्ति पूरी तरह संकल्पित और तैयार है।

भ्रष्टाचार का शिष्टाचार

– अवनीश सिंह की रिपोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले से जुड़े मुद्दे पर फैसला सुनाने के साथ ही 2 फरवरी 2012 को सरकार की साख पर करारा तमाचा जड़ दिया। पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दबाए रखने के मामले में किरकिरी झेल चुकी सरकार को शीर्ष अदालत ने बड़ा झटका देते हुए राजा के कार्यकाल में दिए गए स्पेक्ट्रम के 122 लाइसेंसों को गैरकानूनी और असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया। सरकार की आवंटन नीति को बेजा ठहराते हुए अदालत ने स्पेक्ट्रम की हिस्सेदारी बेच कर मोटा मुनाफा कमाने वाली कंपनियों एतिसलात, यूनिटेक व टाटा टेली पर पांच–पांच करोड़ तथा लूप टेलीकाम, एसटेल, एलायंज इन्फ्राटेक तथा सिस्तेमा श्याम पर 50–50 लाख का जुर्माना भी ठोंका।

जस्टिस ए. के. गांगुली के लिए गुरुवार का दिन भले ही कोर्ट में आखिरी दिन रहा मगर उनका यह फैसला ऐतिहासिक बन गया है। इससे न सिर्फ कॉरपोरेट कानून प्रभावित होगा, बल्कि लंबे समय में इसका असर सरकार की नीति और कॉरपोरेट के कामकाज पर भी होगा। 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला केंद्रीय सत्ता के लिए एक और शर्मिंदगी का क्षण है।

यह महज दुर्योग नहीं हो सकता कि उसके सामने ऐसे क्षण बार–बार आ रहे हैं। अभी दो दिन पहले ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री कार्यालय को कठघरे में खड़ा किया था। खास बात यह है कि उस फैसले के केंद्र में भी पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा ही थे और ताजा फैसले में भी। 2जी स्पेक्ट्रम के सभी 122 लाइसेंस अवैध करार देकर उन्हें रद्द करने के शीर्ष अदालत के फैसले ने यह साबित कर दिया कि जब घोटालेबाज ए. राजा कुछ कारपोरेट घरानों से मिलकर मनमानी करने में लगे हुए थे तब केंद्रीय सत्ता सोई हुई थी। इससे साफ है कि स्पेक्ट्रम आवंटन की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही है और इसमें घोटाला हुआ है।

इस घोटाले के लिए संप्रग सरकार की सामूहिक विफलता को इंगित करना सर्वोच्च न्यायालय नहीं भूला। इसका आशय है कि घोटाले के लिए पूरी सरकार जिम्मेदार है और वह अपने आपको इससे अलग नहीं कर सकती। दुख, क्षोभ और लज्जा की बात यह रही कि जब उसे झकझोर कर इस महाघोटाले से अवगत कराया गया तो उसने शुतुरमुर्गी आचरण का परिचय दिया। इतना ही नहीं उसकी ओर से हरसंभव तरीके से राजा का बचाव करने की भी कोशिश की गई।

यह सर्वविदित है कि सरकारी ठेके और लाइसेंस देने में भ्रष्ट तरीके अपनाए जाते हैं, कानून तोड़े जाते हैं, पक्षपात होता है और आमतौर पर जो कंपनी ज्यादा देती है, उसे ज्यादा मिलता है। गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय ने 122 टेलीकॉम लाइसेंस इसलिए रद्द कर दिए, क्योंकि इन्हें जारी करते समय नीतियों का ठीक पालन नहीं हुआ और भ्रष्ट मंत्री ने रिश्वत लेकर लाइसेंस बांटे। पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने किसी नीति और उसकी खामियों पर सीधी टिप्पणी की है। कोर्ट ने 'पहले आओ–पहले पाओ' नीति को गलत और घातक करार दिया है। रद्द होने वाले लाइसेंस को लेकर बहुत लोगों को चिंता है, और इसके दूरगामी प्रभाव भी होंगे।

अगर लाइसेंस आवंटन में नीति का सही तरीके से पालन नहीं होता है तो भविष्य में यह फैसला लाइसेंस रद्द करने का आधार बन सकता है। आने वाले वर्षों में अनेक मामलों में इस फैसले को नजीर बनाकर उपयोग किया जाएगा। कानून की थोड़ी जानकारी रखने वाला भी यह समझ सकता है कि भविष्य में बड़े कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो सकते हैं। खासकर अगर नीति का सही–सही पालन नहीं हुआ हो तो। फ्रॉड के आधार पर लाइसेंस रद्द करने के कई फैसले हुए हैं।

यह स्वान टेलीकॉम जैसी कंपनियों को सिर्फ लाइसेंस खरीद और बेचकर मुनाफा कमाने से रोकेगा। इस कंपनी ने 1,537 करोड़ रुपये में लाइसेंस खरीदा और एतिसालात को 4,500 करोड़ में हिस्सेदारी बेच दी। यह फैसला राजनीतिज्ञों को भी नीतियों के गलत इस्तेमाल या उनकी गलत व्याख्या करने से रोकेगा। नीति पर अमल हो, इस पर अब नेताओं से ज्यादा कॉरपोरेट्स को चिंता होगी। दूरसंचार मंत्री के पद पर रहते हुए ए. राजा ने कंपनियों को आशय पत्र जमा करने के लिए सिर्फ 45 मिनट का समय दिया। यही नहीं, 1600 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी के लिए भी उन्हें कुछ घंटे का ही वक्त मिला।

सबसे दुर्भाग्यपूर्ण समय वह था जब खुद प्रधानमंत्री ने राजा को क्लीनचिट देते हुए किसी तरह के घोटाले से इंकार किया। इसके बाद जब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने घोटाले पर मुहर लगा दी तो सच को स्वीकार करने के बजाय इस संवैधानिक संस्था की ही खिल्ली उड़ाने का काम किया गया। यह काम सरकार ने भी किया और उसका नेतृत्व करने वाली कांग्रेस ने भी। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद बुरी तरह शर्मसार सरकार के पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन वह अभी भी खुद के सही होने और अपनी सेहत पर फर्क न पड़ने का दंभ भर रही है। इससे तो यही लगता है कि उसने यह ठान लिया है कि कुछ भी हो जाए वह सच का सामना करने के लिए तैयार नहीं होगी। यह और कुछ नहीं बल्कि बची–कुची साख गंवाने का सुनिश्चित रास्ता है।

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद सारी गलती राजा पर थोपने के साथ ही स्पेक्ट्रम आवंटन की गलत नीति बनाने के लिए जिस तरह भाजपा से माफी मांगने के लिए कहा गया वह हास्यास्पद भी है और केंद्रीय सत्ता के अहंकारी रवैये का नमूना। केंद्र सरकार जान बूझकर इस तथ्य की अनदेखी कर रही है कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पेक्ट्रम आवंटन के मामले में राजग सरकार की 'पहले आओ, पहले पाओ' नीति को त्रुटिपूर्ण करार देने के बावजूद संप्रग सरकार के इस तर्क को खारिज कर दिया कि 2008 के पहले के लाइसेंस भी खारिज किए जाने चाहिए।

यह समझना कठिन है कि केंद्र सरकार ने बदली हुई परिस्थितियों में स्पेक्ट्रम आवंटन की नीति को दुरुस्त करने की जरूरत क्यों नहीं समझी और वह भी तब जब इसकी मांग भी की जा रही थी?क्या राजग शासन द्वारा तय की गई नीति कोई पत्थर की लकीर थी? मौजूदा दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल की मानें तो सारी गड़बड़ी राजा ने की। उन्होंने ही रातोंरात नियम बदले और जब वह ऐसा कर रहे थे तो न तो वित्तमंत्री का उन पर कोई जोर चल रहा था और न ही प्रधानमंत्री का। क्या यह कहने की कोशिश की जा रही है कि दूरसंचार मंत्री के रूप में राजा प्रधानमंत्री और कैबिनेट से भी अधिक शक्तिशाली थे? निःसंदेह ये कुतर्क सच्चाई स्वीकार करने से बचने के लिए दिए जा रहे हैं।

जहां तक प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग का संबंध है तो यह प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में विपक्ष का अधिकार होता है कि वह सरकार के कामकाज की समीक्षा करे और उसके गलत कामों की निंदा करे और हरसंभव तरीके से सरकार पर दबाव बनाए, लेकिन यहां सवाल पूरे देश की जनता और संसद के साथ–साथ सुप्रीम कोर्ट के प्रति सरकार की जिम्मेदारी का भी है, जिसे हर हाल में पूरा किया जाना होगा और उस पर खरा उतरना होगा। कम से कम 2जी मामले में सरकार इन पैमानों पर खरी नहीं उतरी है। इससे न केवल सरकार की किरकिरी हो रही है, बल्कि उसके साथ–साथ पूरे देश की छवि भी अंतरराष्ट्रीय जगत में दांव पर लग रही है।

यह एक चिंता की बात है कि देश की सरकार ही देश के लिए समस्या बन रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक नजीर के रूप में लिया जाना चाहिए और आगे के लिए सबक लेते हुए एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आम जनता के लिए बहुत ही राहत लेकर आया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए यह मील का पत्थर साबित होगा। आखिर केंद्र सरकार और उसके रणनीतिकारों को अपनी भूल स्वीकार करने में संकोच क्यों हो रहा है?

पुणे : अभाविप के विरोध के कारण 'सिंबायोसिस' में आयोजित कश्मीर सेमिनार रद्द

पुणे : छद्म बुद्धिजीविता का ढोंग रचकर भारत विरोधी कार्य करने का प्रचलन देश में बढ़ता चला जा रहा है। इसकी एक झलक हाल ही में पुणे के प्रतिष्ठित 'सिंबायोसिस कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स' में देखने को मिली। यहां 'कश्मीर की आवाज' विषय पर होने वाले सेमिनार में राष्ट्रीय भावनाओं के विपरित बनी फिल्म के प्रदर्शन के कोशिश की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की पुणे इकाई व विस्थापित कश्मीरी हिन्दुओं के संगठन पनून कश्मीर के विरोध के चलते 'जश्न–ए–आजादी' नामक इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को दिखाने की कोशिश सफल नहीं हो सकी तथा अभाविप के विरोध के चलते कॉलेज प्रशासन को कश्मीर विषय पर होने वाले इस तीन दिवसीय सेमिनार व फिल्म के प्रदर्शन को रद्द करना पड़ा।

हिंसाग्रस्त कश्मीर के अलगाववादी तत्वों के विचारों का चित्रण करने वाली इस फिल्म में भारतीय सेना व इसके जांबाज सैनिकों को अत्याचारी दिखाने का निंदनीय प्रयास किया गया है जबकि हजारों मौतों के जिम्मेदार व लाखों कश्मीरी पंडितों को घाटी से निकालने वाले पृथकतावादियों को नायक के रूप में परोसने की कोशिश की गई है। कश्मीर की मध्यस्थता करने के नाम पर अलगाववादी बयान देने वाले दिलीप पांडगांवकर सहित कई अन्य तथाकथित बुद्धिजीवी इस भारत विरोधी कार्यक्रम में शिरकत करने वाले थे।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के स्थानीय कार्यकर्ताओं को जब इस फिल्म के प्रदर्शन की सुचना मिली तो पुणे महानगर मंत्री प्रवीण उन्द्रे के नेतृत्व में फिल्म के दिखाए जाने के कार्यक्रम का विरोध किया तथा इस संबंध में कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन भी सौपा। नगर मंत्री प्रवीण उन्द्रे ने बताया कि कॉलेज प्रशासन ने जब राष्ट्रीय भावना व सेना के खिलाफ बनी इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाई तो कुछ लोगों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बहाना बनाकर इस घृणित प्रयास के पक्ष में बयानबाजी की तथा फिल्म को दिखाए जाने की वकालत भी की। लेकिन प्रश्न यह है कि कश्मीर समस्या की वास्तविकता दिखाए जाने के नाम पर आतंकी अलगाववादियों को हिरो बताना किस अभिव्यक्ति की आजादी है? फिल्म उस आजादी को दिखाने का साहस क्यों नहीं करती जिसको लाखों कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार करके छिना गया है?

इस प्रकार के कार्यक्रमों को यू. जी. सी. द्वारा धन मुहैया कराने की नीति का विद्यार्थी परिषद् विरोध करती है।

महाराष्ट्र प्रदेश सहमंत्री शैलेन्द्र दलवी ने कहा कि इससे पहले भी पुणे इकाई ने भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति तथा राष्ट्रवादी भावना को बचाए रखने के लिए एमटीवी के एंकरों को कालिख पोतने, नक्सल समर्थक डॉ. विनायक सेन के कार्यक्रम का विरोध करने एवं भ्रष्ट सुरेश कलमाड़ी के जेल से छूटकर घर आने पर प्रदर्शन करने का काम किया। भारत विरोधी कार्यक्रम को विद्यार्थी परिषद् कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी तथा भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजनों का कड़ा विरोध करेगी।

जीवंत भारत के लिए संकल्पबद्ध हुए युवा

'थिंक इंडिया' का सम्मेलन बेंगलुरू में संपन्न

बेंगलुरू के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स में आयोजित दो दिवसीय 'थिंक इंडिया' सम्मेलन में प्रख्यात व्यक्तियों ने आई आई टी, आई आई एम, और राष्ट्रीय विधी विश्वविद्यालयों (NLU) जैसे प्रमुख संस्थानों के छात्रों को आलोकित किया। प्रमुख संस्थानों के छात्रों के मंच 'थिंक इंडिया' द्वारा आयोजित इस सम्मेलन की थीम 'जीवंत राष्ट्र के लिए दृष्टि' (Vision for Vibrant India) यह थी। भारत के विभिन्न संस्थानों में सर्वोच्च आई आई टी, आई आई एम, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों समेत कुल 27 संस्थानों के 200 से ज्यादा छात्र, शोधकर्ता, पूर्व छात्रों ने इसमें भाग लिया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स के डीन प्रो. पी. आर. महापात्रा ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया और अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. मिलिंद मराठे ने इसकी अध्यक्षता की।

दो दिवसीय इस सम्मेलन में मुख्य वक्ता सात विषयगत सत्र रहे। जिसमें DRDO के पूर्व महानिदेशक प्रो. वी. के. अत्रे, इंफोसिस के संस्थापक निदेशक श्री मोहनदास पै, काले धन के विशेषज्ञ और आई आई एम बेंगलुरू के प्रो. आर. वैद्यनाथन, सुपर 30 के श्री आनंद कुमार, प्रख्यात समाजसेवी डॉ. गिरीश कुलकर्णी, NLSUI बेंगलुरू के कुलपति प्रो. वेंकटराव, NIT के सुरत्कल के निदेशक प्रो. संदीप संचेती, विख्यात विचारक श्री राममाधव, राज्य तथा सभा सांसद श्री बाल आपटे, प्रतिष्ठित युवा वैज्ञानिक डॉ. तथागत अवतार तुलसी, अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुनील आंबेकर, श्री वाय. बी. रामकष्ण, आई आई टी, मद्रास के डीन प्रो. एल. एस. गणेश और आई आई एम बेंगलुरू के प्रो. जी रमेश ने छात्रों को संबोधित किया।

पेपर प्रेसेंटेशन, विशेषज्ञ–कामयाब तथा रोल मॉडेल्स के साथ विचार–विमर्श और 'भारत के रंग' नाम का कल्पात्मक नाटक इसके विशेष आकर्षण रहे। 'थिंक इंडिया 2012' में फोटोग्राफी, पोस्टर, आइडिया इम्पैक्ट, निबंध लेखन, लघु फिल्म और नुक्कड़ नाटिका ऐसी विभिन्न प्रतियोगिताएं संपन्न हुई जिसमें दो लाख रुपये के पुरस्कार भी दिए गए।

उद्घाटन भाषण में भारतीय विज्ञान संस्थान (IISC) के डीन प्रो. पी. आर. महापात्रा ने कहा एक तरफ हमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विकास के क्षेत्र की उपलब्धियों पर गर्व महसूस करते हैं और दूसरी तरफ ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अभी तक विकास के फल भी नहीं चखे, यह हमें भारत के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है। अपने अध्यक्षीय भाषण में अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. मिलिंद मराठे ने प्रमुख संस्थानों के छात्रों को, जो भारत के बेहतरीन संस्थानों में पढ़नें का विशेषाधिकार रखते हैं, अपनी जिम्मेदारी से अवगत कराया। अभाविप का परिचय देते हुए उन्होंने उसके उद्देश्य, दृष्टि तथा छात्र आंदोलन के दर्शन को समझाया। सम्मेलन के संयोजक तथा आई आई एस सी छात्र संघ के अध्यक्ष श्रीवत्स कोलाथयार ने स्वागत भाषण किया। थिंक इंडिया के संयोजन आशीष चौहान ने प्रतिनिधियों को थिंक इंडिया का परिचय करवाया। आई आई एम बेंगलुरू SAC की अध्यक्ष और थिंक इंडिया 2012 की सहसंयोजिका कु. रिमा मुखर्जी ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

प्रख्यात वकील और राज्यसभा सांसद श्री बाल आपटे ने कुशलतापूर्वक 'भारत को समझो'

(Understanding India) यह विषय सभी के सम्मुख रखा। दुनिया के सामने आज जो मुद्दे हैं उसमें भारतीय सभ्यता प्रश्न नहीं बल्कि समाधान है इस पर उन्होंने प्रकाश डाला। भारत के गौरवशाली विरासत और उपलब्धियों को गिनाते हुए आज हमारी ताकत– लोकसंख्या को ठीक से उपयोग में लाने पर उन्होंने जोर दिया। आई आई टी लखनऊ के फैकल्टी डॉ. एम. के. अवस्थी ने इस सत्र की अध्यक्षता की।

विख्यात विचारक श्री राम माधव ने 'समकालीन भारत में भारत के लिए चुनौतियां एवं अवसर' यह विषय प्रस्तुत किया। उन्होंने आज के परिप्रेक्ष्य में भारत के लिए प्रतिस्पर्धी आंतरिक राजनीति–कूटनीति रणनीति के प्रयोग पर जोर देते हुए हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जोसेफ ने के 'कठीण शक्ति और नरम शक्ति' के सिद्धांत को उद्धृत किया। कर्नाटक राज्य ज्ञान आयोग के अध्यक्ष डॉ. एम. के. श्रीधर ने इस सत्र की अध्यक्षता की।

दिल को छू लेने वाले सत्र में 'सुपर 30' के संस्थापक श्री आनंद कुमार ने, 'स्नेहालय' के संस्थापक डॉ. गिरीष कुलकर्णी, 'अक्षयपात्र' के संस्थापक श्री मोहनदास पै ने भारत के सामने के मुद्दों को गिनाया तथा उनसे निपटते हुए अपनी असली जीवन कहानियां बयां की। आनन्द कुमार ने गरीबी और शिक्षा की प्यास के विकल्प के रूप में 'सुपर 30' परिवार स्थापना की कहानी सभी के सम्मुख रखी। प्रसिद्ध समाजसेवी डॉ. गिरीष कुलकर्णी ने मानव तस्करी, देहव्यापार, महिला सेक्स वर्कर और उनके बच्चों के उत्थान हेतु स्नेहालय के चल रहे कार्य की जानकारी दी। इन्फोसिस के संस्थापक निदेशक और 'अक्षयपात्र' के संस्थापक श्री मोहनदास पै ने कर्नाटक में शासकीय विद्यालयों के लाखों छात्रों की भूख मिटाने के बारे में 'अक्षयपात्र' की पहल की यशस्वी दास्तां सुनायी। डॉ. किशोर (NIMHANS) ने इस सत्र का संचालन किया।

'21वी सदी के भारत के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचार' इस विषय पर DRDO के पूर्व निदेशक प्रो. वी. के. अत्रे और प्रसिद्ध वैज्ञानिक और शिक्षाविद् श्री श्रद्धालु रानडे द्वारा सोचा खिजलानेवाला सत्र हुआ। डॉ. तथागत अवतार तुलसी ने इस सत्र की अध्यक्षता की। प्रो. अत्रे ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचारों (Innovation) में उन्नति में उन्नति के लिए देश के भीतर शैक्षिक शक्ति का लाभ उठाने के लिए व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया। डॉ. रानाडे ने भारतीय मन की प्रतिभा, जो अभी पूरी तरह से उपयोग नहीं हुई है, के बारे में बात की। प्रतिष्ठित युवा वैज्ञानिक डॉ. तथागत अवतार तुलसी ने इस सत्र में समापन भाषण दिया।

'प्रशासन और भ्रष्टाचार' पर हुए सत्र में आई आई एम बेंगलुरू में फायनान्स के प्रो. वैद्यनाथन ने भ्रष्टाचार के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए उसके शासन की नीतियों के साथ संबंध स्पष्ट किए। अभाविप के राष्ट्रीय संगठनमंत्री श्री सुनील आंबेकर ने लोकपाल विधेयक के परे चर्चा को ले जाते हुए भ्रष्टाचार की बुराई से निपटने के लिए बुनियादी सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

'सतत विकास' पर हुए सत्र में जैव ईंधन (Bio-Fuel) टास्क फोर्स के अध्यक्ष श्री वाय. वी. रामकृष्ण ने ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को उपयोग करने पर आग्रह किया। आई आई टी चेन्नई के प्रो. एल. एस. गणेश ने अपने जीवनशैली को पनर्परिभाषित करते हुए विकास की अवधारणा की समीक्षा करने की बात कही।

देश के राष्ट्रीय और प्रमुख संस्थानों में आवश्यक शैक्षणिक बुनियादी ढांचा, अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ावा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में राष्ट्रीय नीतियों के बारे में हुए चर्चा सत्र में NLSIU के कुलपति प्रो. आर. वेंकट राव, आई आई एम बेंगलुरू के सहायक प्राध्यापक श्री जी. रमेश, NTK सुरत्कल के प्रभारी निदेशक प्रो. संदीप संचेती ने अपने विचार रखे।

दो दिवसीय 'थिंक इंडिया' सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता आई आई टी मुंबई के प्रो. वरदराज बापट ने की तथा अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुनील आंबेकर ने प्रतिनिधियों को संबोधित किया। श्री श्रीवत्स कोलाथयार ने धन्यवाद ज्ञापन किया। सभी प्रतिनिधि सिर्फ भारत के बारे में नहीं तो 'विकसित और जीवंत भारत' के बारे में सोचने का संकल्प लेते हुए विदा हुए।

उठो पार्थ, गांडीव संभालो!

✍ प्रो. राकेश सिन्हा

भ्रष्टाचार भस्मासुर बनकर भारत के संसदीय जनतंत्र की वैधता एवं विश्वसनीयता को ही चुनौती दे रहा है। जब प्रधानमंत्री भ्रष्ट नौकरशाहों, मंत्रियों एवं व्यवस्था का बचाव करें तथा स्वयं को गुनाहगार मानकर भी अपना कार्यकाल पूरा करने का दावा करें तो इसका दुःखद पहलू संसदीय जनतंत्र का मात्र अपमान ही नहीं, इसका डंके की चोट पर किया जा रहा अवमूल्यन है। भ्रष्टाचार ने सभी परंपरागत सीमाओं को पार कर लिया है। अब तो कोशिश की जा रही है कि इसे भी 'आर्थिक सुधार' का एक पहलू मानकर स्वीकार कर लिया जाए। तभी तो सर्वोच्च न्यायालय को प्रधानमंत्री पर भी टिप्पणी करनी पड़ी।

चरम सीमा पर भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचार अपनी चरम–सीमा पर है। कांग्रेस नेतृत्व ने देश की करीब 125 करोड़ जनता की रोजी–रोटी, अस्मिता, फटेहाली को पूंजीवादी व्यवस्था की नीयत एवं नियति पर छोड़ दिया है। मुट्ठी भर लोग धनतंत्र एवं शासनतंत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर चुनावी राजनीति को सिर्फ वैधता के लिए उपयोग करना चाहते हैं। महात्मा गांधी, पं. दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया जैसे चिंतकों ने धन के केंद्रीकरण को जनतंत्र के लिए घातक माना था। गांधी ने राजनीतिक ताकत एवं धन दोनों के विकेन्द्रीकरण को ही अपने दर्शन का मूलाधार बनाया था, लेकिन गांधी की चिंता आज के कांग्रेसी नेतृत्व को क्यों हो, जब उनके वारिस माने जाने वालों ने ही उनके दर्शन को कूड़ेदान में डालने में तनिक भी शर्म–लज्जा महसूस नहीं की।

आजादी के बाद गांधी ने महसूस किया था कि ब्रिटिश औपनिवेशिक चाल–चलन जारी है। जिस देश में अधिकांश लोगों के सिर पर छत नहीं हो, घरों में शौचलाय न हो, उस देश में राजसी शान–शौकत के साथ राजनेता जीवन व्यतीत करें यह अनैतिक, अमर्यादित और पीड़ादायक नहीं तो और क्या है? गांधी ने इस गिरावट को पहचान लिया था। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिखा था कि 'हम लोग ब्रितानी फिजूलखर्ची की राह पर जा रहे हैं जिसे देश बर्दाश्त नहीं कर सकता है।'

नेहरू की सत्ता का रंग

उन्होंने प्रस्ताव रखा कि वायसराय विशाल भवन (जो अब राष्ट्रपति भवन है) को छोड़कर किसी साधारण भवन में रहें और इस भवन को और भी अधिक उपयोगिता के लिए उपयोग किया जाए। अंग्रेज वायसराय माउंटबेटन ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। गांधी ने तज्ञता व्यक्त करते हुए उन्हें लिखा था कि 'आपने गांवों में रहने वाले अर्ध–अकाल से ग्रस्त लाखों लोगों के गवर्नर जनरल के रूप में साधारण भवन में रहने की इच्छा जताकर अति प्रशंसनीय कार्य किया है।'

लेकिन पंडित नेहरू को यह स्वीकार नहीं था। बातों के धनी नेहरू ने यह कहकर इसे रोक दिया कि 'जब हम लोग दूसरे कामों में व्यस्त हैं तब माउंटबेटन के लिए उपयुक्त घर ढूंढना एवं उसकी व्यवस्था करना संभव नहीं है।' राजनीतिक सत्ता ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। महात्मा गांधी के निधन के तुरंत बाद नेहरू 17 यॉर्क रोड से कई एकड़ में बने तीन मूर्ति भवन में रहने चले गए। तया जिनकिन ने इस पर टिप्पणी करते हुए 'चैलेन्जेज इन इंडिया' पुस्तक में लिखा है कि 'वे हमेशा सादगी से रहने की बात करते थे और स्वयं तीन मूर्ति भवन में रहने गए जो ब्रिटेन द्वारा दिल्ली में बनाए गए भवनों में सबसे अधिक आलीशान था।'

चाहे पाश्चात्य चिंतक प्लेटो हों या भारतीय चिंतक कौटिल्य, सभी ने राजनीति में गिरावट की प्रवृत्ति होने को यथार्थ माना था। यह गिरावट ऐशोआराम से शुरू होकर भाई–भतीजावाद, घोर व्यक्तिवाद एवं भ्रष्टाचार जैसी बुराइयों में तब्दील हो

जाती है। गांधी हों या श्री गोलवलकर, सभी ने राजनीति में फिसलन को अवश्यंभावी मानते हुए उस पर नियंत्रण की आवश्यकता पर बल दिया। यह बात सभी देश–काल में कमोबेश लागू होती रही है।

गांधी जी का सुझाव

कांग्रेस के संविधान में बदलाव के लिए उप समिति बनी थी। गांधी ने सुझाव दिया था कि कांग्रेस को चुनावी राजनीति से अलग हटकर लोक सेवक संघ में परिणत कर देना चाहिए। अपनी मृत्यु से कुछ घंटे पूर्व ही उन्होंने अपने इस विचार–सुझाव को लिपिबद्ध किया था। वे जानते थे कि कांग्रेस में सत्तावादी लोग त्याग–तपस्या, सादगी के पर्याय बने कार्यकर्ताओं को न सिर्फ हाशिये पर ला खड़ा कर देंगे, बल्कि कुसंस्कृति को भी उन पर थोपने का कार्य करेंगे। वे मानते थे कि राजनीति को सशक्तता के साथ गैर–राजनीतिक आंदोलन द्वारा नियंत्रित करना चाहिए तभी इसका निरंतर परिष्कार होता रहेगा। गांधी का यह मत प्रजातांत्रिक व्यवस्था को न सिर्फ सुदृढ़ करने वाला, बल्कि इसे लोकहितवादी बनाए रखने वाला था। गांधी ने स्वयं इस नैतिक नियंत्रण का परिणाम देखा एवं दिखाया भी।

1935 में भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत छह प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। गांधी सत्ता में बैठे लोगों की सादगी एवं चरित्र के प्रति चौकन्ने थे। यह सरकार 1937 से 1939 तक रही। नैतिक निगरानी के प्रभाव एवं दबाव में इन सरकारों में भ्रष्टाचार के उदाहरण खोजने पर भी नहीं मिलते हैं। गांधी का मानना था कि सत्ता का उपयोग मानवता की सेवा के लिए होना चाहिए।

कांग्रेस में भ्रष्टाचार की नींव

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे श्री शंकरराव देव ने 1949 में तीन आत्मालोचक लेख लिखे जिन्हें कांग्रेस के भीतर प्रसारित किया गया। इन अप्रकाशित लेखों में श्री देव ने जिन प्रसंगों को उठाया था, वह अपने आप में उस समय के लिए एक बड़ी बात थी। 15 जुलाई, 1949 को लेख की दूसरी किस्त में श्री शंकरराव देव ने लिखा कि 'अधिकांश कांग्रेसियों ने गांधीजी को राजनीतिज्ञ के रूप में देखा न कि नैतिक नेतृत्व के रूप में।'

भ्रष्टाचार की नींव कांग्रेस शासन ने गणतंत्र की घोषणा से पूर्व ही रख दी थी। तभी तो देव ने सीधे शब्दों में लिखा कि 'पिछले द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान लोग कालाबाजारी, भ्रष्टाचार, घूसखोरी एवं जमाखोरी जैसी बुराइयों से जूझते रहे और वे कांग्रेस को आशा की नजर से देखते रहे कि वह उन्हें इन प्रताड़ना एवं परेशान करने वाले बोझ से मुक्त करेगी, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें निराश होना पड़ा क्योंकि दोनों व्यवस्थाओं में उन्होंने इन मामलों में नाममात्र का परिवर्तन पाया है। भ्रष्टाचार और कालाबाजारी नैतिक बुराई है, जिससे यदि शीघ्र छुटकारा नहीं मिला तो राष्ट्र अपना चरित्र खो देगा। लोगों ने तो यह कहना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस का हाल चीन के कुओमितांग की तरह होगा।' उल्लेखनीय है कि चीन के भ्रष्ट कुओमितांग शासक स्वार्थी एवं संवेदनहीन थे और अंततः उनका सत्ता ही नहीं इतिहास से भी सफाया हो गया।

शंकरराव देव क्यों असंतुष्ट थे? वे इतने कठोर शब्दों में क्यों आगाह कर रहे थे? देव एक कर्मठ गांधीवादी थे। सत्ता उनकी महत्त्वाकांक्षा नहीं थी। वे सत्ता को संयमित करना चाहते थे। उन्होंने लिखा था कि भ्रष्टाचार के प्रश्न पर गांधी कठोर रुख अपनाते थे। 12 जनवरी, 1948 में गांधी ने अपनी प्रार्थना सभा में वी. के. वैंकटपैया गुरु का पत्र पढ़कर सुनाया था जिसमें विधायकों एवं कुछ मंत्रियों के भ्रष्टाचार का उल्लेख था। यह पत्र पार्टी के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को भेजा गया। यहीं से शुरुआत होती है एक नई परंपरा। सरकार में भ्रष्टाचार दलीय विषय बन गया। दल के भीतर का भ्रष्टाचार एवं संसदीय पार्टी और सरकार में भ्रष्टाचार के बीच अंतर पाटने की कोशिश निरंतर होती रही और संसदीय जनतंत्र में पक्ष एवं विपक्ष के बीच तेरा–मेरा भ्रष्टाचार का तुलनात्मक भजन बनकर रह गया। सत्ता, सार्वजनिक अवसरों, वितरण के सिद्धांतों का दुरुपयोग अपने या किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के लिए जब होता है तब व्यवस्था में लोगों की आस्था टूटने लगती है। संगठन का घोषित आदर्श और इसके कार्यकर्ताओं का अनाचार, अनैतिक एवं भ्रष्ट व्यवहार एक विरोधाभासी स्थिति पैदा करता है।

भ्रष्टाचार बना व्यावहारिकता

व्यावहारिकता के नाम पर भ्रष्टाचार किस प्रकार अपना स्थायी घर बना लेता है इसका एक प्रसंग नेहरू युग का है। 'नेशनल हेराल्ड' समाचारपत्र का दिल्ली संस्करण शुरू करने की योजना बनी। तय हुआ कि 5 लाख रुपया इकट्ठा किया जाए। रफी अहमद किदवई ने हिमालय ऐर्वाच्स के मालिक से 25–25 हजार की रकम दो बार वसूल की और बदले में उसे अपने विभाग का ठेका दे दिया। सरदार बल्लभ भाई पटेल ने इसका विरोध कर इसे भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाला कार्य माना। उन्होंने नेहरू को पत्र लिखकर इस पर आपत्ति जतायी थी। नेहरू का जवाब था कि धर्मार्थ कार्य के लिए इकट्ठा किया गया धन अलग माना जाना चाहिए। तब पटेल ने 'नेशनल हेराल्ड' के प्रकाशन को धर्मार्थ कार्य मानने पर आश्चर्य व्यक्त किया था। एम. आर. जयकर ने अपने आत्मचरित्र में जो लिखा है वह दृष्टांत भी सार्वजनिक जीवन में प्रदूषण की ओर इंगित करने वाला था।

संस्थागत रूप

जयकर ने गांधी को खिलाफत आंदोलन के लिए 25 हजार रुपया चंदा दिया था। चंदा मोतीलाल नेहरू के हाथों में आया था। बाद में उन्होंने जयकर से पूछा कि क्या वे अपने अखबार (इंडिपेंडेंट) की वित्तीय कठिनाई दूर करने के लिए कुछ कर सकते हैं? जयकर के शब्दों में 'कुछ दिन बाद मोतीलाल मेरे घर आए और कहने लगे कि मुझे एतराज न हो तो वे गांधी जी को दिए गए रुपये का इस्तेमाल 'इंडिपेंडेंट' समाचार पत्र की वित्तीय कठिनाई को दूर करने में कर लें। मोतीलाल की यह बात सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि मैंने अपनी तरफ से तो रुपया दे ही दिया है। गांधीजी जैसे चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में मुझे यह जानकर बहुत दुःख हुआ कि उक्त सारी रकम को इंडिपेंडेंट अखबार हजम कर गया, लेकिन बदले में मुझे मोतीलाल की दोस्ती अवश्य मिली।' इस व्यावहारिकता को ताकत तब मिली जब सत्ता अनावरण का भी दलीयकरण हो गया। नेहरू युग में चौधरी ब्राह्म प्रकाश, प्रताप सिंह कैरों, टी. टी. कृष्णामाचारी, बख्शी गुलाम मोहम्मद आदि राजनेताओं का दलीय समर्थन मिलता रहा और उनका आचरण भी दलीय स्वार्थ का एक आयाम बन गया। यह परंपरा आज संस्थागत रूप ले चुकी है।

सत्ता का शीर्ष आचरण समाज के लिए मिसाल पेश करता है। वही आचरण राजनीति एवं नौकरशाही की राह बन जाती है। इस देश में सत्ता से जुड़ा राजनीतिक भ्रष्टाचार दिन–प्रतिदिन के जीवन से जुड़ा होने के कारण जनाक्रोश को जन्म देता है। राजनीतिक प्रतिष्ठान नौकरशाही के भ्रष्टाचार के प्रति आंख मिचौली का खेल–खेलकर स्वयं को सफेदपोश बताने का काम करता रहा है। अर्थात् भ्रष्टाचार का आदि और अंत कथाकार प्रेमचंद का 'नमक का दारोगा' है। राजनेता राज्य की तकनीक एवं ताकत का उपयोग इसी उद्देश्य से करते रहे।

इसका एक रोचक एवं आंखें खोलने वाला उदाहरण है। लंदन के भारतीय उच्चायोग में एक कर्मचारी को दंडित कर जेल भेज दिया गया था। उसका अपराध था कि उसने महात्मा गांधी स्मृति पोस्टेज टिकट (जिसका मूल्य एक हजार रुपया था) को 'गंभीर क्षति' पहुंचाई थी। दूसरी तरफ लंदन में ही बैठे भारत के उच्चायुक्त कृष्ण मेनन ने 'जीप घोटाले' में न सिर्फ लाखों की क्षति पहुंचाई बल्कि भारत की सुरक्षा को भी दांव पर लगा दिया। भारतीय सेना के लिए तीन हजार जीपों की आवश्यकता थी। एक हजार नई जीपें अमरीका से खरीदी गईं और कृश्ण मेनन के प्रभाव में मरम्मत की गयी 2000 पुरानी जीपें ब्रिटेन से खरीदी गयीं। ये भी उसी दाम पर खरीदी गयीं जिस पर अमरीका से नई जीपें खरीदी गयी थीं। लेकिन मेनन को नेहरू 'पवित्र गाय' की तरह बचाते रहे। उस 'अभागे' कर्मचारी एवं 'भाग्यवान' मेनन की तुलना करते हुए संसद की लोक लेखा समिति ने अपनी पहली रपट में लिखा था कि 'यह अत्यंत ही खेदजनक बात है कि एक ही विभाग में क्षति की घटनाओं को विरोधाभासी तरीके से निपटाया गया। इस हद तक कि वर्तमान केस (जीप कांड) में कोई कार्रवाई नहीं की गई।'

पृष्ठ कमांक 18 पर...

'विश्व की सभी समस्याओं का हल है भारत'

— मा. सुरेश सोनी

मंच पर बाएं से अजय शर्मा, अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुनील आंबेकर, रा. स्व. संघ के सह सरकार्यवाह मा. सुरेश सोनी, जम्मू-कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष विरेन्द्र कौंडल तथा प्रदेश मंत्री राघव शर्मा

जम्मू-कश्मीर : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जम्मू-कश्मीर इकाई ने 9 जनवरी, 2011 को जम्मू क्लब में पूर्व कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। पारीवारिक उत्सव के समान भावपूर्ण माहौल में आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहकार्यवाह माननीय सुरेश सोनी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुनील आंबेकर और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. नरेन्द्र सिंह रैना ने दीप प्रज्ज्वलित कर दी। इस अवसर पर विद्यार्थी परिषद को देशभक्ति के माहौल में अनुशासित युवाओं को तैयार करने वाला संगठन बताते हुए मुख्य अतिथि सुरेश सोनी ने कहा कि युवाओं के बदौलत ही पूरी दुनिया समाज के सभी क्षेत्रों में भारत को नेतृत्व करते देख रहा है। मजबूत पारिवारिक मूल्य व इसकी सिद्धांतों से भारत विश्व की सामाजिक, आर्थिक व आध्यात्मिक समस्यओं का हल देगा, ऐसा दुनियां को उम्मीद है। भोगवादी जीवन शैली को 2008 में आए विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत इसलिए आर्थिक संकट से अछुता रहा क्योंकि यहां भोग की नहीं बचत की प्रवृत्ति थी। उन्होंने विद्यार्थी परिषद से 21वीं सदी के युवा भारत में नैतिक रूप से मजबूत व अनुशासित युवाओं को राष्ट्र के विकास हेतु तैयार करने में अपनी महत्ती भूमिका निभाने की अपेक्षा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुनील आंबेकर ने विद्यार्थी परिषद द्वारा सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र के बुराइंयों को मिटाने में किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने 'यूथ अगेंस्ट करप्शन' द्वारा चलाए जा रहे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को विद्याथी परिषद के भ्रष्टाचार मुक्त भारत के संकल्प का हिस्सा बताया।

जम्मू-कश्मीर विद्यार्थी परिषद के पिछले 50 वर्षों के कार्यों एवं उपलब्धियों को बताते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. नरेन्द्र सिंह रैना ने अमरनाथ भूमि आंदोलन व केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए किए गए आंदोलन में परिषद की प्रभावी भूमिका बताई।

इस अवसर पर प्रांत अध्यक्ष डॉ. विरेन्द्र कौंडल ने धन्यवाद ज्ञापन किया एवं नगर मंत्री राघव शर्मा ने जम्मू महानगर का वृत रखा। कार्यक्रम में मुख्यरूप से प्रांत संघचालक ब्रिगेडियर सुचेत सिंह, प्रांत प्रचारक रमेश पप्पा, प्रांत कार्यवाह पुरुषोत्तम दधिचि, परिषद के उतर क्षेत्र संगठन मंत्री श्रीनिवास जी, अशोक खजुरिया, डॉ. राकेश शर्मा सहित अनेक पूर्व कार्यकर्ता सपरिवार उपस्थित थे।

विदेशी तथा स्वदेशी दृष्टि में शिवाजी

✍ डॉ. सतीश चन्द मित्तल

शिवाजी के अभूतपूर्व विजय अभियान तथा स्वराज्य स्थापना की सफल योजना भारतीय इतिहास में तत्कालीन क्रूरतम शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता का सफल आंदोलन था। उस आंदोलन ने न केवल भारत के सम्राट अत्याचारी शासक औरंगजेब के साम्राज्य को 19 साल तक झकझोर कर रखा बल्कि बीजापुर के आदिलशाह तथा जंजीरा के सिद्दियों को भी हिला दिया। भारत में यूरोपीय शक्तियों–गोवा तथा दमन के पुर्तगालियों, सूरत व राजापुर के अंग्रेजों, चिन्सुरा के डचों तथा पांडिचेरी के फ्रांसीसियों को भी आतंकित कर दिया।

इतना ही नहीं शिवाजी के 1680 ई. में देहावसान के पश्चात भी अंग्रेजों ने कई महीनों तक शिवाजी को मृत स्वीकार नहीं किया। तभी से शिवाजी का नाम भारतीय इतिहास में एक जय घोष बन गया।

सतत् संघर्ष के स्फूर्ति केन्द्र

1680 से लेकर भारत की आजादी तक शिवाजी संघर्षकर्त्ताओं की प्रेरणा के केन्द्र बन गये। शिवाजी का वह सफल आंदोलन बाजीराव, बालाजी बाजीराव के काल में इतना देशव्यापी हो गया कि मुगल सम्राट मराठा सरदारों की कृपा के दास बन गये। राघोबा के नेतृत्व में मराठों ने जहां पेशावर में भगवा ध्वज लहरा दिया तथा सिन्धु नद पर अपने घोड़ों को पानी पिलाया वहीं दक्षिण में कावेरी तक विजय पताका फहराई। अंग्रेजों ने मराठों से भयभीत होकर जहां कोलकाता के चारों ओर खाई खुदवाई, वहीं मुम्बई के चारों ओर सुरक्षा पंक्ति खड़ी की। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शीघ्र ही शिवाजी का नाम राष्ट्रवाद का पर्याय बन गया।

1857 के महासमर में शिवाजी प्रेरक तत्त्व बने रहे। बासुदेव बलवंत फड़के तो स्वयं अपने को दूसरा शिवाजी मानते थे। महाराष्ट्र में एक शिवाजी दल बना जिसने महाराष्ट्र के ब्रिटिश गर्वनर सर रिचर्ड टैम्पल का सर काटकर लाने पर 500 रुपये का पुरस्कार रखा था। इन्हीं क्रांतिकारी घटनाओं के भय से ए. ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। परंतु लोकमान्य तिलक ने शिवाजी का राज्याभिषेक उत्सव मनाकर 'स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है' का उद्घोष किया। भगत सिंह तथा अन्य क्रांतिकारियों के लिए शिवाजी मार्गदर्शक बन गये। सावरकर ने देश की आजादी के लिए शिवाजी का तरीका उपयुक्त बताया। सुभाष चन्द्र बोस ने देश की स्वतंत्रता का एकमात्र मार्ग बतलाया– शिवाजी–शिवाजी और शिवाजी।

शिवाजी पर विदेशी साहित्य

शिवाजी का जीवन इतना प्रभावी रहा कि उनके जीवनकाल में तथा बाद में उनके क्रियाकलापों पर देश–विदेश में अनेक ग्रंथों की रचना हुई। वे सदैव विदेशों में जिज्ञासा, कौतुहल तथा भय का विषय बने रहे। सर्वप्रथम भारत में पुर्तगालियों के आगमन से यूरोपीय शक्तियों की भारत में घुसपैठ शुरू हुई थी। भारतीयों की उदारता का लाभ उठाकर उन्होंने सूरत से लेकर गोवा तक 400 मील की समुद्री पट्टी पर कब्जा कर लिया था। 1695 ई. में अर्थात् शिवाजी की मृत्यु के 15 वर्ष पश्चात पुर्तगाली भाषा में शिवाजी के जीवन पर 168 पृष्ठों का एक ग्रंथ लिखा गया, जो तथ्यपूर्ण नहीं है। लिस्बन स्थित पुर्तगाली

अभिलेखागार में भी शिवाजी पर कोई सरकारी प्रपत्र नहीं है। लिस्बन स्थित पुर्तगाली बस्तियों के एक प्रमुख व्यक्ति सेनोर–द–गार्दा ने शिवाजी के साहसिक कार्यों का वर्णन इस प्रकार किया है – 'यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि शिवाजी अपनी जगह पर दूसरे व्यक्ति को बैठा देता है या वह एक जादूगर है अथवा राक्षस'।

शिवाजी पर अंग्रेजी साहित्य

शिवाजी के जीवनकाल में अंग्रेजों को अनेक कटु अनुभव आये थे। समय–समय पर वे शिवाजी को भेंट देते रहते थे परंतु उनमें सर्वदा भय व्याप्त रहता था। 17 वीं तथा 18 वीं शताब्दी में शिवाजी पर किसी अंग्रेज द्वारा कोई पुस्तक नहीं लिखी गई पर उस काल के कंपनी के दस्तावेजों से शिवाजी के जीवन पर कुछ प्रकाश अवश्य पड़ता है।

1663 ई. में शाइस्ता खां के पूना से भागने पर एक अंग्रेज प्रतिनिधि ने लिखा–

'ऐसी खबर मिली है कि शिवाजी हवा में उड़ता रहता है और उसके पंख भी हैं। अन्यथा उसके लिए असंभव है कि एक समय में ही वह कई स्थानों पर मौजूद रहे। उसके अनोखे करतबों के कारण उसकी चर्चा समाज के हर क्षेत्र में हुआ करती है।'

सूरत के एक अंग्रेज व्यापारी ने लिखा, 'शिवाजी सच्चा मित्र है, श्रेष्ठ शत्रु है और अत्यंत चतुर राजा।'

1678 ई. शिवाजी के कर्नाटक अभियान के बाद एक अंग्रेज ने लिखा–

'उसने (शिवाजी) अपने ईश्वर के सम्मुख यह प्रतिज्ञा की है कि जब तक दिल्ली नहीं पहुंच जाता और औरंगजेब को बंदी नहीं बना लेता, वह अपनी तलवार को म्यान में नहीं रखेगा। यह प्रसिद्ध है कि शिवाजी द्वितीय सरटोरियम है और अपनी चतुर सैनिक चालों में हैनीवाल से कम नहीं है।'

1680 ई. में मुम्बई व्यापार कंपनी के अध्यक्ष ने कोलकाता के अध्यक्ष को लिखा–

'शिवाजी इतनी बार मर चुका है कि उसके मरने का विश्वास ही नहीं होता, उसे लोग अमर ही समझते हैं–...अब हम उसे मरा हुआ तब समझेंगे, जब तक कि उसके समान साहसपूर्ण काम करने वाला मराठों में कोई नहीं होगा और हमें मराठों के पंजों से छुटकारा मिलेगा।'

इटालियन तथा फ्रांसीसी यात्री

चिन्सुरा के डचों द्वारा शिवाजी का कोई वर्णन नहीं मिलता। इटली के यात्री मनूची की शिवाजी से 1665 ई. में राजा जयसिंह से भेंट के समय लम्बी वार्ता हुई थी, जो उसने अपने संस्मरणों में दी है। फ्रांसीसी यात्री बरनियर ने शिवाजी की सूरत की लूट तथा बीजापुर के संबंधों के बारे में लिखा–'यह पुरुष शिवाजी स्वतंत्र राजा के समान संपूर्ण प्रभुत्व से कार्य कर रहा है। यह मुगल और बीजापुर के सुल्तान की भर्त्सना पर हंसता है...अपने साहसी और सतत प्रयत्नों से वह औरंगजेब का ध्यान अपनी ओर खींचता है...औरंगजेब के लिए यह महत्त्वपूर्ण विषय हो गया है कि शिवाजी का दमन किस प्रकार करे'। इसी भांति फ्रांसीसी पादरी टेवरनियर, थेवेनाट, फ्रांसिस मार्टिन ने भी शिवाजी के वीरतापूर्ण जीवन पर प्रकाश डाला है।

स्वदेशी साहित्य

शिवाजी के जीवन पर वर्तमान प्रसिद्ध इतिहासवेत्ताओं–यदुनाथ सरकार, सर जी. एस. देसाई, नरसिंह चिंतामणि केलकर ने बहुत प्रकाश डाला है। शिवाजी के काल में कवि भूषण ने शिवराज भूषण की रचना की थी जिसके छंद आज भी वीरता तथा शौर्य की भावना पैदा करते हैं। यदुनाथ सरकार ने शिवाजी को एक महान संगठक बताते हुए लिखा है कि 'मराठा जाति अपने उदय से पूर्व छोटे–छोटे अणुओं की भांति दक्षिणी रियासतों में बंटी हुई थी। उसने (शिवाजी) उन्हें एक मजबूत राष्ट्र में बांध दिया. .. किसी अन्य हिन्दू ने आधुनिक युग में उतनी प्रतिभा का परिचय न दिया था।' शिवाजी का सही मूल्यांकन करते हुए यदुनाथ सरकार ने 1928 में मद्रास में अपने भाषण में कहा था–'राज्यों का पतन होता है, साम्राज्य टूटते हैं, वंश नष्ट हो जाते हैं, परंतु शिवाजी जैसे एक

पृष्ठ क्रमांक 13 से निरंतर...

जीतना है यह युद्ध

महात्मा गांधी ने 1946 में टी. प्रकाशम को आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का विरोध किया था। उसका कारण था कि प्रकाशम ने आंध्र की जनता द्वारा दिए गए तीस हजार रुपए का उपयोग अपने निजी जीवन के लिए किया था। गांधी का मानना था कि सार्वजनिक व्यक्ति को कुछ भी भेंट उसकी निजी हैसियत के आधार पर नहीं की जाती है। विरोध करने पर प्रकाशम ने तीस हजार रुपया पार्टी को देने का निर्णय लिया। गांधी ने उनसे पूछा वे पैसे किस प्रकार इकट्ठा करेंगे तो प्रकाशम का उत्तर था कि कोई भी धनी व्यक्ति उन्हें यह रकम देने के लिए तैयार है। गांधी इसे भ्रष्टाचार मानते थे।

नैतिकता का यही मापदंड आज अव्यावहारिक घोषित कर दिया गया है। राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई संसद के प्रांगण में तभी संभव है जब मजबूत जनमत की घेराबंदी होगी, जब घेराबंदी टूटती है तो छद्म लड़ाई चलती है। मापदंडों को तात्कालिक लाभ–हानि के सिद्धांत से अलग कर उसे कठोरता के साथ लागू करने में ही भलाई है। कांग्रेस ने राजनीतिक भ्रष्टाचार का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है उसके दो आयाम हैं–पहला कांग्रेस में गिरावट, दूसरा वर्तमान आर्थिक नीति में अन्तर्निहित भ्रष्टाचार के विषाणु। मृत्युशैया पर पड़ी कांग्रेस को सच्ची श्रद्धाञ्जलि वैकल्पिक व्यवस्था के आह्वान में है। इस व्यवस्था की पात्रता, नेतृत्व एवं नैतिकता का मापदंड तीनों ही पार्थ का गांडीव होगा। और यह गांडीव उठाना होगा देश के जनमानस को, क्योंकि आज वही पार्थ की भूमिका में है और उसे ही अनैतिकता के विरुद्ध देशहित में यह युद्ध जीतना है।

सच्चे नेता सम्पूर्ण मानव जाति के लिए एक अद्वितीय देन के रूप में रहते हैं।'

परंतु अपने देश में अब भी कुछ बौने इतिहासकार हैं जो सेकुलरवाद के भ्रमजाल में शिवाजी की तुलना मतान्ध औरंगजेब से करते हैं। हर समय घोड़े की पीठ पर रहने वाले शिवाजी तथा पालकी में बैठकर युद्ध में जाने वाले औरंगजेब की कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है। अब भी कुछ विद्वान मुगल शासकों तथा शिवाजी को एक समान बताने में अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं। आश्चर्य है कि सीबीएसई की भारतीय इतिहास की पुस्तकों में शिवाजी पर केवल एक दो पंक्ति ही दी हैं और वह भी नकारात्मक (देखें कक्षा सात की पुस्तक, पृ.–49) 12वीं की इतिहास की पुस्तक, जिसके तीनों भाग 536 पृष्ठों के है, में शिवाजी का नाम भी नहीं दिया गया। यह एक गंभीर प्रश्न है कि हम भारतीय इतिहास में देश की नवयुवक पीढ़ी को शिवाजी जैसे बहुआयामी तथा राष्ट्र पुरुष के अध्ययन से वंचित रख रहे हैं। अतीत के महापुरुषों को भुलाकर क्या राष्ट्र की प्रगति होगी? क्या राष्ट्र का भविष्य उज्ज्वल होगा? हम कब तक कल्पनालोक में विचरण करते रहेंगे? देश के सजग पाठकों तथा युवा पीढ़ी को इस पर विचार करना होगा। शिवाजी जैसे महापुरुष को इतिहास से निकालना राष्ट्रघातक होगा। यह भारतीय इतिहास का उपहास होगा। आवश्यकता है हम राष्ट्रीय महापुरुषों से प्रेरणा ले राष्ट्र को उन्नत, सुदृढ़ तथा बलशाली बनाएं।

(19 फरवरी शिवाजी जयंती के उपलक्ष्य में यह लेख)

प्रिय मित्रों,

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधी पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' का फरवरी अंक आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। इसमें विभिन्न समसमायिक घटनाकमों तथा भ्रष्टाचार से संबंधित कई महत्वपूर्ण आलेखों एवं खबरों का संकलन किया गया हैं। आशा है यह अंक आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा।

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव एवं विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई–मेल पर अवश्य भेजें।

"छात्रशक्ति भवन"
690, भूतल, गली नं. 21,
फैज रोड, करोलबाग,
नई दिल्ली – 110005.
फोन : 011–43098248
ई–मेल : chhatashakti.abvp@gmail.com,
वेबसाईट : www.abvp.org

निहित स्वार्थ व वंशवादी राजनीति के वर्चस्व हेतु बंद है छात्र संघ चुनाव- उमेश दत्त

मुजफ्फरपुर : 'छात्रों के समस्यायों के लिए लड़नेवालें प्रतिभाशाली छात्र नेताओं की जगह, वंशवादी राजनैतिक वर्चस्व स्थापित करने हेतु बिहार में छात्र–संघ चुनाव बंद करवाए गए हैं। छात्र संघ चुनाव न होने की वजह से शैक्षणिक परिसर लुट–खसोट व भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् छात्र संघ चुनाव करवाने हेतु सड़क से सदन तक सतत संघर्ष करेगी एवं छात्रों को उनके लोकतान्त्रिक अधिकार दिलाएगी।'

उक्त बातें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के राश्ट्रीय महामंत्री श्री उमेश दत्त ने 22 जनवरी को बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के सीनेट हॉल में 'छात्र संघ चुनाव : छात्रों का लोकतान्त्रिक अधिकार' विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए कही। छात्र संघ चुनाव को स्वाभाविक नेतृत्व उभारने का माध्यम बताते हुए श्री उमेश दत्त ने कहा कि 'लोकतंत्र की जननी बिहार मे छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो छात्रों को उनके लोकतान्त्रिक अधिकारों से वंचित कर रही है। बिहार की सत्ता एवं सम्पूर्ण विपक्ष की बागडोर छात्रसंघ चुनाव में जीतें व छात्र आंदोलनों की उपज नेताओं के पास है परन्तु निहित स्वार्थी मानसिकता से जकड़े व वंशवादी राजनीति के पक्षधर नेता छात्र संघ चुनाव नहीं करवाना चाहते। हिंसा का बहाना बनाकर छात्र संघ चुनाव न करवाने की दलील को खारिज करते हुए श्री उमेश दत्त ने लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुरूप अविलम्ब चुनाव करवाने की मांग की। छात्रसंघ को छात्र समस्यायों के समाधान का मंच बताते हुए प्रान्त संगठन मंत्री श्री निखिल रंजन ने कहा कि बिहार में छात्र संघ व छात्र राजनीति समाप्त करने की साजिश रची जा रही है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया व उसके मूल्यों के विपरीत है। श्री रंजन ने राज्य सरकार पर छात्र संघ चुनावों के प्रति उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया तथा छात्र संघ चुनावों हेतु पुरे प्रदेश में आन्दोलन चलाने की बात कही। सेमिनार को संबोधित करते हुए सीनेटर श्री मुकुल शर्मा ने शैक्षणिक परिसर में छात्र संघ चुनाव न होने से होने वाली परेशानियो पर प्रकाश डालते हुए कहा कि चुनाव न होने से शिक्षा माफिया की सक्रियता बढ़ गयी है। राश्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य डॉ. विनोद राय ने युवाओं की सामाजिक गतिविधिओं एवं राजनीति में भागीदारी बढ़ाने हेतु चुनाव की वकालत की। सेमिनार की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष डॉ. वेणु राय, धन्यवाद ज्ञापन जिलाप्रमुख प्रा.विनय कुमार तथा संचालन जिलासंयोजक केशरी नंदन शर्मा ने किया।

स्वामी जी के विचारों को आत्मसात करे युवा - देवेन्द्र भसीन

देहरादून : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई देहरादून द्वारा युवाओं के प्रेरणास्रोत स्वामी विवेकानन्द के 149 वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर डी. ए. वी. कॉलेज देहरादून में उनके विचारों की एक प्रदर्शनी व साहित्य की स्टॉल भी लगाई गई जिसका उद्घाटन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. देवेन्द्र भसीन ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. भसीन ने विद्यार्थी परिषद् द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की सराहना की तथा युवाओं को विवेकानन्द के विचारों को आत्मसात करने का आह्वान भी किया।

अभाविप के प्रदेश अध्यक्ष ने विद्यार्थी परिषद् द्वारा स्वामी विवेकानन्द के विचारों को शोभायात्रा, विचार प्रदर्शनी, संदेश यात्रा के माध्यम से पहुंचाने के कार्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सही मार्गदर्शन हेतु युवाओं को विवेकानन्द द्वारा बताए गए रास्ते पर चलना चाहिए। धन्यवाद ज्ञापित करते हुए महानगर अध्यक्ष डॉ. डी. के शाही ने भारत को विश्व में अग्रणी स्थान पर पुनः स्थापित करने के लिए स्वामीजी के विचारों से राष्ट्रहित में कार्य करने की अपील युवाओं से की। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश सहमंत्री आशीष बहुगुणा ने किया।

जम्मू-कश्मीर पर बिछी सतरंज की बिसात

✍ डॉ. कुलदीप चन्द अग्निहोत्री

भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है जम्मू-कश्मीर को लेकर चल रहे विदेशी षडयंत्रों को परास्त करना। भारत माता के मुकुटमणि कश्मीर के प्रति देशवासियों की जाग्रत शक्ति के द्वारा ही इस समस्या का समाधान हमेशा के लिए किया जा सकता है। अतः कश्मीर के प्रति अलगाववादियों व राष्ट्रद्रोहियों द्वारा निर्माण किए जा रहे भ्रमों से परे वास्तविकता को समझना अत्यंत आवश्यक है। पाकिस्तान की रणनीति इस विषय को अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर जिंदा रखने की है। लेकिन उसकी यह रणनीति भारत सरकार के सहयोग के बिना पूरी नहीं हो सकती । भारत सरकार की सामान्य बुद्धि की दाद देनी पड़ेगी कि वह पाकिस्तान की इस रणनीति में अपनी भूमिका पूरी शिद्दत से निभाती रहती है। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान अपनी इस रणनीति की सफलता के लिए आज तक प्रायः अमरीका समेत अन्य गोरी साम्राज्यवादी शक्तियों पर निर्भर करता रहा है।

भारत सरकार की अदूरदर्शिता

भारत का विभाजन ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर हुआ था। इस अधिनियम ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को भी वैधानिक तौर पर आत्मसात किया था। अधिनियम में रियासतों के राजाओं को भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने की छूट दी गयी थी। अधिनियम में किसी भी स्तर पर दोनों देशों में शामिल होने की प्रक्रिया में वहां की जनता को शामिल नहीं किया गया था। कानूनी तौर पर विलय की प्रक्रिया में जनता के समर्थन अथवा विरोध की कोई वैधानिक महत्ता नहीं थी। भारत स्वतंत्रता अधिनियम में रियासती राजाओं को विलय के लिए किसी समयसीमा का निर्धारण भी नहीं किया गया था। अधिनियम की इन धाराओं को लेकर बहस हो सकती है। लेकिन जब तक कोई अधिनियम अपने अस्तित्व को बनाए रखता है तब तक उसके अनुसार किए गए कृत्य ही वैधानिक माने जाते हैं। जम्मू-कश्मीर रियासत के भारत में विलय को इसी दृष्टि से देखना होगा। रियासत के उस वक्त के राजा महाराजा हरिसिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और 27 अक्टूबर 1947 को विलयपत्र को भारत के गवर्नर जनरल ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार रियासत के भारत में विलय की प्रक्रिया पूरी हुई। यह सुविदित है कि उस समय इंग्लैंड सरकार नहीं चाहती थी कि जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय हो। इंग्लैंड की इच्छा जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान में देखने की थी। पाकिस्तान सरकार तो मजहब के आधार पर जम्मू-कश्मीर को प्रारम्भ से ही अपना हिस्सा मानकर चल रही थी। यह तो खुदा का शुक्र है कि जम्मू-कश्मीर भारत के ब्रिटिश भूभाग का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक रियासत थी, नहीं तो इंग्लैंड इसे पहले ही पाकिस्तान को सौंप देता। जब पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों की ही इच्छाओं के विपरीत रियासत के राजा ने उसका भारत में विलय कर दिया तो ये दोनों शक्तियां तुरंत सक्रिय हो गयीं। यह सक्रियता दो मोर्चों पर हो रही थी। पहला मोर्चा तो जम्मू-कश्मीर पर पाकिस्तान का प्रत्यक्ष आक्रमण ही था, जिसे बहुत से ब्रिटिश इतिहासकारों और बाद में भारतीय इतिहासकारों ने भी सीमांत प्रांत के कबाइलियों का भी आक्रमण कहा है। लेकिन अब यह निर्विवाद सिद्ध हो गया है कि कबाइलियों के मुखौटे में पाकिस्तान की सेना ही पूरी व्यूह रचना कर रही थी। दूसरा मोर्चा पूरे विलय को लेकर ही विवाद खडा करना था। इसमें उस वक्त के भारत के गवर्नर जनरल तुरंत सक्रिय हुए । ये गवर्नर जनरल भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए भी प्रत्यक्षतः ब्रिटिश एजेंट ही थे। उन्होंने विलय पत्र स्वीकार करते ही तुरंत महाराजा को एक चिट्ठी लिखी जिसमें भारत सरकार की ओर से यह घोषणा की गयी कि चूंकि जम्मू-कश्मीर रियासत का विषय विवादास्पद है इसलिए विलय को अंततः जनमत द्वारा ही तय किया

जाएगा। गवर्नर जनरल के साथ –साथ उस समय के भारतीय प्रधानमंत्री ने भी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली को एक लम्बा तार दिया कि कश्मीर के विलय का प्रश्न क्योंकि विवादों से घिरा हुआ है इसलिए इसका अंतिम निर्णय रियासत की जनता का मत जानकर ही किया जाएगा। स्पष्ट है कि पाकिस्तान ने भारत के गवर्नर जनरल को अपने पक्ष में करके विलय के विवादास्पद होने की चर्चा प्रारम्भ करवा दी थी और भारत के प्रधानमंत्री गवर्नर जनरल के पीछे–पीछे पूरी तरह इस जाल में फंस चुके थे।

संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका

भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जो शिकायत भेजी थी , वह स्पष्ट ही एक सीमित प्रश्न को लेकर थी और संयुक्त राष्ट्र संघ का अधिकार क्षेत्र भी कानूनी रूप से उसी सीमित क्षेत्र पर निर्णय देने तक था। यह प्रश्न था कि भारत पर पड़ोसी देश पाकिस्तान ने आक्रमण किया है, इसलिए उसे आक्रांता घोषित किया जाए और उसे भारतीय क्षेत्र में से सेनाएं वापस बुलाने के लिए कहा जाए। इसके विपरीत संयुक्त राष्ट्र संघ ने विलय की वैधता अथवा अवैधता पर विवेचन करना प्रारम्भ कर दिया। और साथ ही कश्मीर में जनमत संग्रह कैसे करवाया जाए, इसके विभिन्न तरीकों पर जरूरत से ज्यादा गंभीर विचार–विमर्श करना शुरू कर दिया। जाहिर था कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपने अधिकार का अतिक्रमण कर रहा था और इस अतिक्रमण के कारण उसके निर्णयों को भारत सरकार को तुरंत अस्वीकार करना चाहिए था और वहां से अपनी शिकायत वापस लेनी चाहिए थी। इसे देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की ओर से दर्ज शिकायत का समर्थन करने के लिए भारत सरकार की ओर से जो प्रतिनिधिमण्डल भेजा गया था उसमें नेशनल कान्फ्रेंस के प्रधान शेख अब्दुल्ला को विशेष रूप से शामिल किया गया था और शेख अब्दुल्ला ने अपने भाषण में विलय का जबरदस्त समर्थन भी किया। लेकिन शेख अब्दुल्ला के भाषण से भारत सरकार ने इस गैर कानूनी कदम को महत्त्वपूर्ण बना दिया कि रियासत में भारत के विलय का मुख्य आधार वहां की जनता का समर्थन है। इसके विपरीत इस शिष्टमण्डल में महाराजा हरिसिंह को शामिल किया जाता तो उससे भारत की कानूनी स्थिति और मजबूत होती। पाकिस्तान और अमरीका दोनों जानते थे कि जनमत वाला मामला इतना फिसलन भरा है कि उसकी जब चाहे मनमानी व्याख्या की जा सकती है और प्रश्न को तद्नुसार उलझाये रखा जा सकता है। यदि भारत सरकार इन निर्णयों को अस्वीकार नहीं करती तो जाहिर है वह इस पूरी अवैधानिक चर्चा में भाग लेने के लिए स्वयं को एकपक्ष के रूप में प्रस्तुत कर रही है। पाकिस्तान और अमरीका की भी यही रणनीति है और अभी तक पता नहीं किन कारणों से भारत सरकार शतरंज की उस बिसात पर एक पक्ष के रूप में बैठकर कश्मीर संबंधी विवाद को जिंदा रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाकर भारतीय हितों के विपरीत ही आचरण कर रही है।

जम्मू–कश्मीर रियासत की भागीदारी

भारत का संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा गठित हुई थी उसमें निमयानुसार रियासतों के प्रतिनिधि भी शामिल किए जा रहे थे। रियासत अथवा रियासत समूह के राजप्रमुख अपनी रियासत की ओर से आबादी के अनुपात में संविधान सभा में सदस्यों का मनोनयन करते थे। मनोनयन का यह अधिकार कानूनी रूप से रियासत के राजा अथवा राजप्रमुख को ही था। अन्य सभी रियासतों के राजाओं अथवा राजप्रमुखों ने अपनी रियासतों की ओर से मनोनयन किया था लेकिन जम्मू–कश्मीर के मामले में शेख अब्दुल्ला ने यह मनोनयन किया और भारत सरकार के दबाव में सदर–ए–रियासत की ओर से नियुक्त रीजेण्ट ने केवल चार व्यक्तियों का नाम दिल्ली तक भेजने में ही भूमिका निभायी। शेख अब्दुल्ला सदर–ए–रियासत की ओर से ही रियासत के प्रशासक अथवा प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे, लेकिन संविधान सभा के लिए चार सदस्यों का चयन करने में रियासत के प्रशासक ने अपनी वैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण किया और दुर्भाग्य से भारत सरकार ने रीजेण्ट पर राजनीतिक दबाव डालकर इस अवैधानिक कार्य को मंजूरी दिलाने का दूसरा अवैधानिक कार्य किया। संविधान सभा में शेख अब्दुल्ला और उनके साथियों द्वारा अवैधानिक ढंग से

घुस जाने के कारण उनकी भारत को 'ब्लैकमेल' करने की शक्ति कई गुना बढ़ गई जिसका परिणाम अभी तक देखा जा रहा है।

पाकिस्तान का अवैध कब्जा

पिछले 64 वर्षों के इतिहास में शायद प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के शासनकाल में पहली बार भारत सरकार ने पूर्व में की गयी अपनी गलतियों और अवैधानिक कृत्यों की विरासत से निकलने का एक ईमानदार प्रयास किया । संसद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके यह संकल्प लिया कि पाकिस्तान द्वारा राज्य के बलपूर्वक कब्जा किए गए हिस्से को मुक्त करवाना ही समस्या का वैधानिक हल है। 1947 में पाकिस्तान ने राज्य के कुछ भागों मसलन बाल्टिस्तान और गिलगित पर कब्जा करने के अतिरिक्त कश्मीर के सीमांत के पंजाबीभाषी क्षेत्र मुजफ्फराबाद और जम्मू संभाग के मीरपुर पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान जिसको 'आजाद कश्मीर' कहता है उसमें कश्मीरीभाषी लोग नहीं हैं बल्कि मुजफ्फराबाद और मीरपुर के पंजाबीभाषी लोग हैं। जिनकी सभ्यता और संस्कृति पंजाब से मिलती है न कि कश्मीर से। गिलगित और बाल्टिस्तान को पाकिस्तान 'आजाद कश्मीर' का हिस्सा नहीं मानता और वह पाकिस्तान में उत्तरी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। पिछले कुछ वर्षों से उत्तरी क्षेत्र में चीनी सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा है। इन सैनिकों की संख्या का अनुमान 10 से 15 हजार के बीच में बताया जाता है। रिकार्ड के लिए पाकिस्तान सरकार इन सैनिकों की उपस्थिति का कारण निर्माण की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बताती है। लेकिन तटस्थ विश्लेषक इसे कश्मीर समस्या में चीन को तीसरा पक्ष बनाने की साजिश मान रहे हैं। गिलगित और बाल्टिस्तान के लोगों का कश्मीर के लोगों के साथ भाषायी अथवा सांस्कृतिक संबंध नहीं हैं। कश्मीर में ज्यादातर लोग सुन्नी मुसलमान हैं जबकि इन उत्तरी क्षेत्रों में शिया हैं। इनकी भाषा तिब्बती भाषा से मिलती जुलती है। यह क्षेत्र मूलतः लद्दाख के अंग थे और यहां के लोग बुद्ध के उपासक थे जो कालांतर में मतांतरण के कारण मुसलमान हो गए। पाकिस्तान सरकार ने समस्या के समाधान के लिए शायद इस क्षेत्र में चीन से सबक लेकर जनसंख्या परिवर्तन का एक नया प्रयोग शुरू किया है। जिस प्रकार चीन तिब्बत में हान लोगों को बसाकर वहां जनसंख्या का अनुपात बदल रहा है। गिलगित और बाल्टिस्तान में भी पाकिस्तान सरकार उसी प्रकार पंजाबियों और पठानों को बसाकर जनसंख्या का अनुपात बदलना चाहती है। इस क्षेत्र में उर्दू को जबरदस्ती लागू करके स्थानीय मातृभाषा को समाप्त करने का षड्यंत्र भी रचा जा रहा है। वैसे तो पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यह भू भाग पिछड़ा हुआ है लेकिन पाकिस्तान सरकार भी इस क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं में पैसा लगाने से गुरेज ही करती है। 'आजाद कश्मीर' में वैसे कहने के लिए तो पाकिस्तान ने वहां एक स्वतंत्र सरकार बना रखी है, परन्तु उसकी हैसियत नगरपालिका जितनी भी नहीं है। यही कारण है कि अब उत्तरी क्षेत्रों में और 'आजाद कश्मीर' के लोगों में पाकिस्तान के प्रति वितृष्णा पैदा हो रही है और विद्रोह की चिंगारियां भी कहीं–कहीं दिखायी देने लगी हैं।

अतीत काल में खड़ी सरकार

लेकिन दुर्भाग्य से भारत सरकार जम्मू–कश्मीर राज्य को लेकर उसी अतीत काल में खड़ी दिखायी दे रही है जिसमें उसे पण्डित नेहरू अपनी अदूरदर्शिता के कारण छोड़ गए थे। विदेश विभाग के अधिकारी उसी सोच से संचालित हैं जो वाशिंगटन और लंदन से प्रचारित और प्रसारित होती है। क्या इसे जम्मू–कश्मीर की त्रासदी ही कहा जाएगा कि कश्मीर पर चर्चा करने वाले और उसका समाधान सुझाने वाले तथाकथित राजनीतिज्ञों और कूटनीतिज्ञों को इस प्रश्न पर लंदन और वाशिंगटन की भाषा तो आसानी से समझ आ जाती है लेकिन उन्हें जम्मू, लद्दाख और कश्मीर के लोगों की भाषा अभी तक समझ में नहीं आ रही। दिल्ली में बैठे लोग कश्मीर को एजेण्टों के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं, यही इस समस्या का मूल कारण है।

बदलेगी गांवों की तस्वीर

मध्यप्रदेश
पंच परमेश्वर योजना

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

अब तक पंचायतों को विभिन्न योजनाओं के
तहत टुकड़ों में राशि मिलती थी,
जिससे गांवों में विकास के काम भी टुकड़ों में होते थे।
'मध्यप्रदेश पंच-परमेश्वर योजना' इस कमी को दूर करेगी।

जनसंख्यावार ग्राम पंचायतों का प्रस्तावित वर्गीकरण	जनसंख्यावार प्रति ग्राम पंचायत प्रस्तावित राशि रुपयों में
2000 तक की ग्राम पंचायत	5 लाख तक
2001 से 5000 तक की ग्राम पंचायत	8 लाख तक
5001 से 10000 तक की ग्राम पंचायत	10 लाख तक
10001 से ऊपर की ग्राम पंचायत	15 लाख तक

अपना राज - पंचायत राज

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

RNI No. 32464/78

Con. No. - DL(N)/249/10-12

ओडिशा में चिदंबरम का विरोध

तिहाड़ से छुटकर पुणे आने पर कलमाडी के घर के सामने प्रदर्शन कर रहे अभाविप कार्यकर्ता